नहीं, इसी के लिए मैं कहना चाहता हूं। यह देखते हुए कि वक्त कम है, मेरा सेकिण्ड सप्लीमेंटरी यह रहेगा कि महाराष्ट्र में गए तीन साल में ऐसे कितने फ्राड हो गए हैं जो शासन के ध्यान में आ गए हैं ? इतना तो बता दीजिए।

SHRI DALBIR SINGH : These cases are, I think, under the JPC. How can I know about these cases ? सर, दूसरी बात है, जहां तक बंकिंग ग्रुप का प्रश्न है It is an entirely separate question अगर माननीय सदस्य गौर से देखें तो यह जो बंकिंग ग्रुप बनी है, यह बैंक आफ बड़ौदा की चेयरमैनशिप में बनी है और जो नान बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स हैं, इनके क्या आगे काम होंगे, किस तरह से इसमें चैक होगा, जो डिपाजिटर्स है, उनकी क्या सिक्यूरिटी रहेगी, इस पर विचार करने के लिए सब-कमेटी गठित हुई थी।

SHRI S. JAIPAL REDDY : Mr. Chairman, Sir, the Minister told the House that the recommendations of the Working Group would be implemented in a phased manner. Will the hon. Minister be so good as to tell the House what the report is all about ? Will the report be placed on the Table of the House ?

Secondly, Mr. Chairman, Sir, why has the RBI not acted at all ? He is making a promise in regard to the future. There is need to see that the nationalised banks ....

SHRI MENTAY PADMANABHAM : There is no time left. Let the Minister reply.

श्री दलबीर सिंह : अभी जो बंकिंग ग्रुप की रिपोर्ट है, अभी सितम्बर, 1992 में आई है और अभी आर० बी० आई० को पेश हुई है। उसको हम देख रहे हैं। उसमें और भी यदि आपके सुझाव आते हैं तो उन पर भी गौर किया जाएगा।

MR. CHAIRMAN : The Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Demand for Merger of DA with Basic Pay

*105. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the unions of Central Government employees have constantly been demanding merger of DA with the basic pay of the employees;

(b) if so, what action Government have taken on their demand;

(c) what is the percentage of DA likely to be merged with pay;

(d) whether the Unions have also demanded for ad-hoc increase in the pay of the employees and creation of a permanent wage body; and

(e) if so, what are the details thereof and what action has been taken thereon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SHANTARAM POTDUKHE) : (a) to (e) The Staff Side in the National Council of the Joint Consultative Machinery (JCM) have, *inter alia,* demanded merger of a portion of Dearness Allowance with the basic pay; 20 per cent increase in the basic pay and the setting up of a Permanent Wage Review Body. These demands have been under discussion with the representatives of the Staff Side and were last brought up in the meeting of the National Council (JCM) held on the 7th November, 1992. It was decided that a meeting of the National Council could be convened some time in April, 1993 to further deliberate on these issues.

Approval of Belthara Road Thermal Power Project

*106. SHRI SANGH PRIYA GAUTAM : Will the Minister of POWER be pleased to state :

(a) whether his Ministry have received the revised plan for the Belthara Road

(Ballia) Thermal Power Project from Uttar Pradesh Government through the Central Electricity Authority for approval, which was sent in November, 1990; and

(b) what is the present position of the project with regard to its techno-economic and environmental clearance, Coal linkage as well as confirmation for movement of coal and oil by the Railways ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI KALPNATH RAI) : (a) and (b) The Revised feasibility report for installation of 3×250 MW Belthara Road Thermal Power Project in the State Sector in District Ballia, U.P. was received in the Central Electricity Authority (CEA) from U.P. State Electricity Board (UPSEB) in November, 1991.

The project can not be considered for techno-economic clearance by the CEA in the absence of essential linkages and clearances such as fuel linkage including its transportation, water availability, associated transmission system, compliance of Section 29 of the Electricity (Supply) Act, 1948, clearance from the Central as well as State authorities from environmental angle. It is for the State Electricity Board to ensure that these are tied up first.

अल्पावधि विद्युत परियोजनाओं का कार्यान्वयन

*107. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अल्पावधि विद्युत परियोजनाओं का कार्यान्वयन संतोषजनक नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान अल्पावधि विद्युत परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के संबंध में किए गए कार्य का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) कम निर्माण अवधि वाली विद्युत परियोजनाओं के मामले में विद्युत उत्पादन हेतु फीडस्टॉक के रूप में सामान्यतया गैस अथवा डीजल का उपयोग किया जाता है । गैस आधारित ताप विद्युत परियोजनाओं और डीजल जनरेटिंग सैटों का केन्द्रीय क्षेत्र में कार्यान्वयन संतोषजनक रहा है । तथापि, राज्य क्षेत्र की कुछ परियोजनाओं के कार्यान्वयन के मामले में विलम्ब हुआ है ।

(ख) निधियों की कमी के अलावा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारणों में निम्नलिखित से संबंधित कठिनाइयां शामिल हैं :—

गैस तथा भूमि की प्राप्ति, संयंत्र एवं उपस्कर हेतु आर्डर दिए जाने संबंधी निर्णय लिए जाने में विलम्ब और उपयुक्त प्रकार की मशीनरी की सप्लाई में विलम्ब ।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान चालू की गई इस प्रकार की अल्प निर्माणावधि वाली परियोजनाओं की राज्यवार सूची विवरण में दी गई है ।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मे० वा०)
उत्तरी क्षेत्र :		
राजस्थान		
1.	अन्ता संयुक्त साइकिल गैस टर्बाइन जी टी–3	88
	एसटी–1	149